भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 864

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

**इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्था के लिए प्रयास**

**864. श्रीमती विजिला सत्यानंत:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन-व्यवस्था हेतु स्थायी तथा दीर्घकालिक नीति, सहायता, ग्राहक केन्द्रित प्रोत्साहन देने और व्यापक रूप से जागरूकता अभियान की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता सोसायटी (एस.एम.ई.वी) सरकार से पूरे भारत में 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कम से कम एक मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखने की आशा करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावड़ेकर)**

**(क)** भारी उद्योग विभाग का वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों तक पहुँचने का कोई लक्ष्य नहीं है।

**(ख) और (ग):** भारी उद्योग विभाग ने एक योजना नामतः "भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण" तैयार की है, जिसमें ई-दुपहिया वाहनों के खरीददारों को मांग प्रोत्साहन देकर अगले तीन वर्षों में एक मिलियन ई-दुपहिया वाहनों की सहायता किए जाने की आशा है।

******